

प्रेषक,

डी०एस० गव्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग-2देहरादून: दिनांक: ७८ अग्रे
मार्च, 2016

विषय:—जनपद चमोली की तहसील कर्णप्रयाग अन्तर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय, गौचर की स्थापना हेतु कुल 8.506 है० भूमि कृषि शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-1528/छब्बीस-21(2015-2016) दि०-21.12.2015 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं०-5363/पांच-भू०ह०/रा०प०-०१५ दि०-०७.०१.२०१६ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम गवाड़ लग्गा भटनगर, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गौचर, तहसील कर्णप्रयाग, जनपद चमोली की यथा प्रस्तावित 5.781 है० तथा ग्राम शैल की यथा प्रस्तावित 2.725 है० इस प्रकार कुल 8.506 है०, श्रेणी-10(4) अकृषित/भीटा राज्य सरकार की भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों के अन्तर्गत तथा कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन की विभागीय सहमति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन कृषि शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1— भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2— जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- 3— हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4— यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5— जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6— जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7— प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

- 8— प्रश्नगत नॉन जेड०ए० भूमि आवंटन के पूर्व जर्मीदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9— इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस०एल०पी०)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं०-436/2011/SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि०-जनवरी, 2011 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10— आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गर्वाल)
सचिव।

पृ०प०संख्या- ५०९ /XVIII(II)/2016-18(09)/2016 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- 4— निजी सचिव, मा० उपाध्यक्ष, विधान सभा उत्तराखण्ड को मा० उपाध्यक्ष, विधान सभा के संज्ञानार्थ।
- 5— निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6— प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
जून २०१८
(जो०पी० जोशी)
अपर सचिव।